प्रसार भारती
भारतीय प्रसारण निगम
आकाशवाणी केन्द्र शिमला
02.01.2026 / प्रादेशिक समाचार / 18:00बजे

मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने राजस्व मामलों का त्वरित व समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने पर बल दिया है। शिमला में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने पांच जनवरी के बाद सभी तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को हर सप्ताह मंगलवार, बुधवार और वीरवार को तकसीम के मामलों की सुनवाई करने के निर्देश दिए ताकि इनका समयबद्ध निपटारा किया जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला उपायुक्त प्रत्येक शनिवार को तकसीम के मामलों की सुनवाई की समीक्षा करेंगे और उसी दिन समीक्षा रिपोर्ट अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व को प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह राजस्व सचिव हर सोमवार को राजस्व मंत्री को विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग से प्रदेश में निजी, वन और सरकारी भूमि का पूर्ण विवरण प्रस्तुत करने के भी निर्देश दिए। बैठक में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार रामसुभग सिंह और मुख्य सचिव संजय गुप्ता सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे जबकि सभी ज़िलों के उपायुक्त वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।

रोहित ठाकुर

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज शिमला जिले के जुब्बल उपमंडल के डकैड़ में निर्माणाधीन शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस संस्थान में प्रदेश व देश भर से शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे जिससे शिक्षा का आधारभूत ढांचा मजबूत होगा। बाद में शिक्षा मंत्री ने खड़ा पत्थर में निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण कार्य का भी निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में स्वास्थ्य के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के उददेश्य से 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण किया जा रहा है।

राजीव बिंदल

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रामीण व गरीब परिवारों के लिए विकसित भारत जी राम जी योजना लागू की है जिसके तहत एक सौ 25 दिन की रोजगार गारंटी दी जा रही है। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार इस योजना को लेकर भी बेतुकी बयानबाजी कर लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है।

बिंदल ने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस व्यवस्था परिवर्तन की बात करती है लेकिन हकीकत में सुक्खू सरकार प्रदेश को व्यवस्था पतन की ओर धकेल रही है।

राजीव बिंदल–

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित गरीब परिवारों के लिए हजारों करोड़ रूपए की राहत राशि प्रदान की और उस राशि को प्रभावितों तक पहुंचाने में भी राज्य सरकार पूरी तरह विफल रही है। बिंदल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस सरकार की गरीब विरोधी नीतियों को उजागर करती रहेगी।

एग्रो स्टॉक योजना

केन्द्र सरकार द्वारा किसानों के उत्थान के लिए एग्रो स्टॉक योजना शुरू की गई है। इस योजना में किसानो को पंजीकरण करवाना अनिवार्य किया गया है और योजना में पंजीकरण न करवाने पर किसानों को किसान सम्मान निधि की प्रतिवर्ष 6 हजार मिलने वाली राशि बंद हो जायेगी। सोलन के जिला कृषि अधिकारी डॉ. अरुण शर्मा ने बताया कि इस योजना में किसान स्वयं भी एग्री हिमाचल पर जाकर पंजीकरण कर सकते है या अपने नजदीकी लोकमित्र केंद्र में निशुल्क पंजीकरण करवा सकते है। अरुण शर्मा ने बताया कि योजना के तहत बनी यूनिक आईडी से किसान अन्य उपदान भी सहजता से ले सकते हैं।

विक्रमादित्य सिंह

लोकनिर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि साहित्यकार समाज को सही दिशा प्रदान करते हैं और उनकी रचनाओं के माध्यम से लोक संस्कृति, भाषा, परंपराएं व रीतिरिवाज पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसारित होती है। शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थियेटर में कल आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने सात पुस्तकों का विमोचन किया।
